महत्वपूर्ण एवं खास

रेत में दबने से दो मज़दूरों की हुई मौत,इलाके में शोक की लहर

कोरबा (आरएनएस)। लाकडाउन के इस काल मे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दर्दनाक घटना प्रकाश में आ रही है यहां 2 लोगों को नदी किनारे से कोयला निकालना भारी पड़ गया। दरअसल नदी के किनारे से कोयला निकालते समय रेत सरकने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। मृतकों को रेत से बाहर निकाला गया। घटना कोरबा शहर को दो हिस्सों में विभक्त करने वाली हसदेव नदी की है। इस हादसे में पुरानी बस्ती माझी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मीन मांझी और 22 वर्षीय शिवलाल माझी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात हसदेव नदी के छोर से कोयला खोदकर निकाल रहे थे। तभी अचानक ऊपर से रेत सरकी और दोनों उसी के नीचे दब गए। सुबह दोनों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई और मृतकों को रेत से बाहर निकाला गया। परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

नक्सली पर्चे में बेचापाल मुठभेड़ को बताया फर्जी

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के बचेली थाना अंतर्गत नेरली क्षेत्र में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों ने बेचापाल मुठभेड़ को लेकर मंगलवार की देर शाम सड़क पर बड़ी संख्या में नक्सली पर्चा फेंक कर मारे गये नक्सली आसू सोढ़ी को नाबालिग बताकर फर्जी मुठभेड़ में निर्मम तरीके से पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। नक्सली पर्चे में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के द्वारा सड़क पर फेंके गये पर्चे में आरोप लगाया है कि 16 अप्रैल को बेचापाल में कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। पुलिस जवानों ने आसू सोढ़ी की निर्मम तरीके से पीट-पीट कर हत्या कर दी। नक्सलियों ने मारे गये नक्सली आसू सोढ़ी को नाबालिग बताया है। जब कि दंतेवाड़ा पुलिस ने 08 लाख का ईनामी नक्सली आसू सोढ़ी उम्र 32 वर्ष निवासी केतुलनार कुटरू जिला बीजापुर नेशनल पार्क एरिया कमेटी सदस्य, एक्सन टीम का कमांड़र के रूप में शिनाख्त उसके परिजनों से करवाई गई थी।

नाबालिक बच्ची के प्रताड़ना-मारपीट पर दर्ज हुई रिपोर्ट

जगदलपुर (आरएनएस)। शहर के बलदेव स्टेट में महेश चांडक परिवार के यहां घर में काम करनें वाली आदिवासी नाबालिक बच्ची को प्रताड़ित और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरूध्द आदिवासी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक बच्ची की जाति प्रमाण पत्र के लिए अब तक पुलिस की कार्यवाही रुकी हुई थी। पुलिस को जाति प्रमाण मिलते ही आरोपियों के विरूध्द आदिवासी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बलदेव स्टेट में रहने वाले महेश चांडक के परिवार पर नाबालिक बच्ची ने प्रताड़ित कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में आदिवासी समाज ने परिवार के दो सदस्यों पर रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। बच्ची के जाति प्रमाण पत्र के लिए आदिवासी एक्ट की धारा लगाने के लिए आगे की कार्यवाही रुकी हुई थी।

तीन पाव अंग्रेजी शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। लाकडाउन में शहर की सारी दुकानें बंद है। बावजूद इसके मदिरा प्रेमी शराब की अवैध तस्करी करने वालों से अपने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। आमानाका थाने से मिली जानकारी के अनुसार सत्यजीत झा आयु 21 वर्ष पिता सदानंद झा निवासी रोटरीनगर आमा नाका से पुलिस ने तीन बाटल अंग्रेजी शराब बरामद की है। उक्त मामले में आमानाका थाने ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत मामला कायम किया है।

जुआरियों से 3 हजार 190 रुपये की राशि जब्त

रायपुर (आरएनएस)। नेवरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार घनश्याम साहू आयु 35 वर्ष पिता सीताराम साहू एवं उनके छह साथी निवासी बैकुंठ बाजार के पास नेवरा के पास खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पाये गये। पुलिस ने मौके पर ही जुआरियों से ताशपत्ती जब्त करते हुए 1580 रुपये की राशि बरामद की। वहीं महेश लोधी आयु 30 वर्ष पिता मानसिंह लोधी एवं अन्य से शर्मा पानी टंकी फैक्ट्री के पास बैकुंठ से खुलेआम जुआं खेलते हुए 1610 रुपये की राशि 52 पत्ती के साथ जब्त की। दोनों मामलों में नेवरा थाने ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत मामला कायम कर कुल 3190 रुपये की राशि जब्त कर आरोपियों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया।

पढ़ई तुंहर दुआर : 15.77 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ

» फीस दबाव की शिकायत पर आठ स्कूलों को नोटिस

» डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग

रायपुर (आरएनएस)। स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने आज वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि 'पढ़ई तुंहर दुआर' कार्यक्रम का लाभ प्रदेश में 15 लाख 77 हजार 351 स्कूली विद्यार्थी को मिल रहा है। इस पोर्टल से एक लाख 65 हजार 245 शिक्षक भी जुड़ चुके हैं। डॉ. टेकाम ने बताया कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की फीस स्थगित करने का निर्णय शासन ने लिया है। बच्चों से शुल्क लेने की शिकायत पर 8 अशासकीय विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सावधानी बरतते हुए स्कूलों में फिजिकल डिस्टेसिंग और आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए सभी स्कूलों को 13 मार्च 2020 लॉकडाउन की श्रेणी में ले लिया था। लॉकडाउन के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए तत्काल कदम बढ़ाते हुए 'पढ़ई तुंहर दुआर' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस कार्यक्रम के अंर्तगत ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ 7 अप्रैल को किया गया। यह पोर्टल बहेबीववसण्पद पर सभी बच्चों के निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 'पढ़ई तुंहर दुआर' कार्यक्रम के पोर्टल में 7 हजार 910 वीडियों, 188 ऑडियो, 3 हजार 477 फोटो, एक हजार 754 कोर्स मटेरियल अपलोड हो चुके हैं तथा 78 ऑनलाईन कक्षाएं संचालित है। यह पोर्टल उच्च शिक्षा के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। 'पढ़ई तुंहर दुआर' कार्यक्रम को काफी सराहा गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी राज्य के बच्चे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है। इसी के साथ बच्चों से सतत् सम्पर्क करते हुए विभिन्न एप के माध्यम से ऑनलाईन कक्षाएं भी प्रारंभ की गई। इस ऑनलाईन प्रक्रिया और पोर्टल से कक्षा पहलीं से 10वीं तक के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. टेकाम ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन हो, इसके लिए विद्यालय में बच्चे एक साथ बैठकर परीक्षा न दे। शासन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कक्षा पहली से आंठवी तक तथा नवमी और ग्यारहवीं कक्षा के सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन दे कर अगली कक्षा में कक्षोन्नति भी दी है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि पर बच्चों का मध्यान्ह भोजन प्रभावित न हो, इसके लिए कक्षा पहली से आंठवी तक के सभी बच्चों के लिए 40 दिन का सूखा अनाज बच्चों को उपलब्ध कराया। प्रदेश में 29 लाख बच्चों में से 98 प्रतिशत बच्चें इसका लाभ उठा रहे है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के पालकों पर आर्थिक भार न पड़े इसके लिए समस्त अशासकीय विद्यालयों के बच्चों से शुल्क लेने की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। साथ ही अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन जारी रखने का निर्देश भी दिया गया है।

गोरखपुर को प्रशासन ने पूरी तरह किया सील

» सैकड़ो लोगो के सेंपल को जांच के लिए भेजा गया रायपुर

पेंड्रा-मरवाही (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित पेंड्रा -मरवाही जिले में पिछले कुछ दिनों से हड़कंप मचा हुआ है। सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में 14 वर्षीय किशोर के कोरोना पॉजिटिव आने से छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से जुड़ने के बाद प्रसासन ने गोरखपुर क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है. इसके साथ ही 100 से अधिक लोगों का सैंपल और करीब 50 लोगों को क्वॉरेंटाइन किया गया है। पुलिस पॉजिटिव आए किशोर और उसके संपर्क में आए लोगों के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तफ्तीश में जुटी है।

कलेक्टर ने बताया कि करंजिया जिला प्रशासन से कोरोनी की पुष्टि होने के बाद से पेंड्रा प्रशासन ने गोरखपुर गांव की सीमाएं हर तरफसे सील कर दिया है।

रिपोर्ट का इंतजार – पॉजिटिव किशोर के सीधे संपर्क में आए 50 से अधिक लोगों को रातों-रात क्वॉरेंटाइन सेंटर भेज दिया. जबकि गांव के 100 से अधिक लोगों की सैंपल लेकर रायपुर जांच के लिए भेजा गया है. उनके रिपोर्ट के आने का इंतजार है।

गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में भी ऐसे ही संक्रमण आया था, कटघोरा आये संक्रमित किशोर के कारण कई लोग संक्रमण का शिकार हुए थे संक्रमण फैलाने वाला किशोर महाराष्ट्र से आया था जोकि निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के व्यक्तियों के संपर्क में आया था।

छत्तीसगढ़ राज्य में 3350 गौठानों की हुई जियो टैगिंग

» पशुओं के नजदीकी गौठान में व्यस्थापन में होगी काफी सहूलियत

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को अब जियो टैगिंग के माध्यम से नजदीकी गौठान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में गौठानों के जियो टैगिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में 3350 गौठानों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इससे ग्रामीणों के लिए अपने पशुओं के नजदीकी गौठान में व्यस्थापन में काफी सहूलियत होगी। जियो टैगिंग करने से न सिर्फ गौठान की लोकेशन की जानकारी मिलेगी बल्कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण जैसे कार्यो के लिए पशु पालकों और पशु पालन विभाग को भी आसानी होगी।

प्रदेश के गौठानों की सटीक स्थिति ज्ञात करने के लिए विभागीय वेबसाइट http://nggb.cg.nic.in में जियो टैगिंग गौठान बटन दबाने पर नक्शे पर गौठान की स्थिति व फोटो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गौठानों का जियो टैग का कार्य पशुधन विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा गौठान स्थान पर भौतिक रूप से पहुंच कर मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर अक्षांश एवं देशांतर अंकित किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश में आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठानों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1929 गौठान पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 10 हजार 5 ग्राम पंचायतों में से 5 हजार 409 ग्राम पंचायतों में गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत गौठानों को पूर्ण करने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। शेष ग्राम पंचायतों में भी गौठानों के काम लगातार स्वीकृत किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के उपरांत शेष गौठानों की भी जिया टैगिंग प्राथमिकता से की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन की

सुराजी ग्राम योजना के तहत राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से गांव-गांव में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी के विकास के काम प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। सुराजी ग्राम योजना के महत्वपूर्ण घटक गरूवा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए गौठान का निर्माण कराया जा रहा है।

दिखने लगा नरवा, गरवा, घुरवा, बारी को सहेजने का असर

» सब्जियां उगाकर और वर्मी कंपोस्ट बेचकर आत्मनिर्भर हो रहीं हैं महिलाएं

» नरवा संवर्धन से जलस्तर में बढ़ोतरी, गौठान ने फसलों को बचाया आवारा मवेशियों से

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारियों को सहेजने की सुराजी गांव योजना का असर अब गांवों में दिखने लगा है। यह योजना खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो दे ही रही है, ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोल रही है। कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉक-डाउन के दौर में भी महिलाएं बाड़ी में सब्जी उगाकर और गौठान में निर्मित वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर कमाई कर रही हैं। ये महिलाएं सब्जियों का वितरण कर ग्रामीणों की मदद भी कर रही हैं।

नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के अंतर्गत भू-जल स्तर सुधार, पशुधन विकास, जैविक खाद निर्माण और बाड़ी विकास के कार्यो के अब सकारात्मक परिणाम दिखना शुरू हो गया है। रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड में करीब डेढ़ हजार की आबादी वाले गांव हिर्री के गौठान में दो महिला स्वसहायता समूह सब्जी उगा रही हैं। श्री ग्राम्य भारती और लक्ष्मी स्वसहायता समूह की 15-15 महिलाएं गौठान की डेढ़ एकड़ बाड़ी में भिंडी, करेला, केला और कद्दू की खेती कर रही हैं। यहां से निकली सब्जियों को अभी लॉक-डाउन में निराश्रितों और जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। बची सब्जियों को बेचकर समूह की महिलाएं जीविकोपार्जन भी कर रही हैं।

हिर्री में कुछ अन्य स्वसहायता समूह की महिलाएं गौठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के काम में लगी हुई हैं। अभी हाल ही में इन महिलाओं ने स्थानीय किसानों को 15 क्विंटल जैविक खाद बेचा है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराने के साथ साथी महिलाओं की बाड़ी के लिए भी वे जैविक खाद देती हैं। जैविक खाद के उपयोग से मृदा और पर्यावरण दोनों की सेहत सुधर रही है। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के दौरान केचुओं का संवर्धन कर इसका भी विक्रय किया जा रहा है। गौठान और बाड़ी में काम के दौरान सभी महिलाएं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपायों का पालन कर रही हैं। साबुन से बार-बार हाथ धोने के साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क या कपड़े से मुंह ढंककर काम कर रही हैं। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत गांव के पास से गुजरने वाले नाले में जल संवर्धन के लिए बोल्डर चेकडैम बनाया गया है। इसके निर्माण से गांव के भू-जल स्तर में काफी सुधार आया है।

छह लाख की अवैध लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त

रायपुर (आरएनएस)। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा और वन्यप्राणियों के अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए सतत् निगरानी रखी जा रही है। इस तारतम्य में प्रधान मुख्य संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य के बलरामपुर वन मण्डल में लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 19 अप्रैल 2020 तक वन अपराध के 180 प्रकरणों में 161 अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें लगभग 6 लाख रूपए की राशि के इमारती आदि लकड़ी के अवैध चिरान और लगभग 7 लाख रूपए की राशि के मोटर सायकिल तथा ट्रॉली सहित ट्रैक्टर की भी जसी की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बलरामपुर वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र कुसमी तथा राजपुर में वन्य प्राणियों जंगली सुअर और चीतल के अवैध शिकार के कारण 9 अपराधियों के खिलाफ वन्य प्राणी, वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय राजपुर में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान वनमंडल बलरामपुर के वन मण्डलाधिकारी डॉ. प्रणय मिश्रा द्वारा गठित टीम द्वारा 9 वन परिक्षेत्रों बलरामपुर, रामानुजगंज, चान्दो, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, वाड्रफनगर, धमनी तथा रघुनाथनगर में 730 नग इमारती लकड़ी के अवैध चिरान सहित 1047 बल्ली आदि जप्त किए गए।

माना में 100 बिस्तर वाला कोविड-19 अस्पताल तैयार

» यहां 24 बिस्तरों के आईसीयू की भी है व्यवस्था

रायपुर (आरएनएस)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर के माना में कोविड-19 के मरीजों इलाज के लिए 100 बिस्तर वाला विशेषीकृत अस्पताल तैयार किया गया है। यहां कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने बताया कि राजधानी रायपुर के नजदीक माना स्थित सिविल अस्पताल को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों के विशेष अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। यहां 24 बिस्तरों का आईसीयू भी बनाया गया है।

श्री बंसोड़ ने बताया कि माना के कोविड-19 हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स सहित कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज की सुविधा सुनिश्चित की गई है। इस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित गर्भवती माताओं की डिलेवरी की भी व्यवस्था है। यह हॉस्पिटल कोविड-19 के इलाज के दौरान बरती जाने वाली सभी आवश्यक सावधानियों और मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां प्रवेश एवं निकास द्वार की पृथक-पृथक व्यवस्था के साथ ही संक्रमितों के उपचार व देखभाल के बाद डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टॉफ के डिसइन्फेक्शन की भी व्यवस्थाएं की गई है। मरीजों की देखभाल एवं उपचार के दौरान चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टॉफ द्वारा उपयोग में लाए गए पीपीई किट, मास्क, ग्लब्स और अन्य सुरक्षात्मक सामग्री को डिस्पोजल के पहले संक्रमण रहित करने का भी इंतजाम इस हॉस्पिटल में है।

प्रदेश कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत के मुख्य संपादक अरनब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया

रायपुर (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामलें में प्रदेश कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत के मुख्य संपादक अरनब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम तथा मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार को रायपुर सिविल लाईन थाने में अरनब गोस्वामी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके आधार पर पुलिस ने अरनब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।

सब्जी, मसाला, फूल उत्पादन से किसानों के जीवन में आएंगी खुशियों की बहार

» आर्थिक लाभ वाले उद्यानिकी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे किसान

रायपुर (आरएनएस)। किसानों में परम्परागत धान फसलों की बजाय सब्जी, मसाला और फूलों की खेती की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के जांजगीर-चांपा जिले में इस वर्ष बड़ी संख्या में किसान इन फसलों की खेती कर रहे हैं। जिले में किसानों के खेतों में 14.005 हेक्टेयर में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। वहीं नदी कछार तटों पर 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसानों द्वारा सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर जिला खनिज न्यास मद से राशि स्वीकृत कर सब्जी-मसाला क्षेत्र और सूक्ष्म व स्प्रिंकल सिंचाई तथा नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी विकास के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा जांजगीर-चांपा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्जी, मसाला, पुष्प उत्पादन और फलदार पौधों का रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों द्वारा योजनाओं का लाभ लेकर बाड़ी में सिंचाई सुविधा को विकसित करने के साथ-साथ सुरक्षा के लिए फेंसिंग कार्य भी किया जा रहा है। गांव में बनाए जा रहे गौठानों में भी फलदार पौधों का रोपण किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य पोषित योजना के तहत जांजगीर में 14.005 हेक्टेयर में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। इसी प्रकार नदी कछार तटों पर 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसानों द्वारा सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 1.5 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) की सुविधा दी गयी है। बाड़ी की सुरक्षा के लिए 7.22 हेक्टेयर में सामुदायिक फेंसिंग का कार्य किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 32.08 हेक्टेयर में फूल सब्जी मसाला व फूलों की खेती की जा रही है। फूल 3.51 हेक्टेयर में सब्जी 21.07 हेक्टेयर में और फूल की खेती 7.5 हेक्टेयर में की गयी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्थक हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रकार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ शासकता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सलाहता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं तकनीकी तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु पर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU